

न्यूज गैलरी

राज्यपाल उड्डे ने संविधान की प्रस्तावना का किया पठन



रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुंधा उड्डे ने संविधान दिवस के अवसर पर राजभवन में संविधान की प्रस्तावना का पठन किया। इस प्रस्तावना में कहा गया है कि 'हम भारत के लोग, भारत को एक संघर्ष प्रभुत्व - संघर्ष समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतन्त्रवाक, गणतन्त्र बनने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अधिकार, विश्वास, धर्म और उपमानी की स्वतंत्रता, प्रशिक्ष और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बेजोबा बढ़ने के लिए दृढसंकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वाारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आचार्यापित करते हैं।

मंत्रालय में बिना मास्क वाले 6 कर्मचारियों से हुई अर्थदण्ड की दसूली

रायपुर। मंत्रालय महानदी भवन में मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों से अर्थदण्ड की दसूली की जा रही है। आज दूसरे दिन मंत्रालय में अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान मास्क नहीं लगाने वाले 6 कर्मचारियों से अर्थदण्ड की दसूली की गई है। इसके पुर 25 नवंबर को बिना मास्क लगाए एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए पाए जाने पर 9 कर्मचारियों को नियमानुसार ज्ञात कर राखी दसूली की गई थी और पहिलिय में बिना मास्क लगाए पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई थी।

लोकजगणी : 'हम सरकार दो वर्ष का कार्यकाल' विषय पर होगी बात

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकजगणी में इस बार 'छत्तीसगढ़ सरकार दो वर्ष का कार्यकाल' विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेगी। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आवासजगणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-2430501, 2430502, 2430503 पर 25, 26 एवं 27 नवंबर को अपरान्ह 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिपोर्ट कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रडियो वार्ता लोकजगणी की 13 वीं कड़ी का प्रसारण 13 दिसंबर को होगा।

धान खरीदी की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा : मुख्यमंत्री के निर्देशों से कराया गया अवगत मुख्यमंत्री ने कहा है धान बेचने में किसानों को न हो कोई परेशानी

रायपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुख साहू एवं खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रताप सिंह ने राज्य के सभी संभागवार, सभी कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और सभी जिला पंचायत के मुख्य कार्यालयन अधिकारियों को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा दिए गए निर्देशों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि धान बेचने में किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

अपर मुख्य सचिवों ने राज्य के सभी कमिश्नरी और कलेक्टरों से कहा कि एक दिसम्बर से राज्य में धान खरीदी शुरू होगी। राज्य में धान खरीदी का कार्य मुख्यमंत्री

श्री भूपेश बघेल की पहली प्राथमिकता है। धान खरीदी में राज्य के किसी भी समिति में किसानों की परेशानी नहीं होनी चाहिए। धान खरीदी के लिए टोकन अधिकतम एक सप्ताह के अवधि तक के लिए दिए जाएंगे। किसानों की जारी टोकन की उद्धिखित तारीख तक किसी

कारणवश यदि कोई किसान धान नहीं बेच पाता है तो उन्हें पुनः नया टोकन जारी किया जाएगा। राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में खतबर्ष से 2 लाख 49 हजार ज्वाट किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीवन कराया है। किसानों का पंजीवन बढ़ने में साथ ही खेती के रकबे में बढ़ोतरी

हुई है। राज्य में गिरदवरी के पछात प्रविष्टि का कार्य 10 नवम्बर को समाप्त हो चुका है। गिरदवरी के संबंध में किसी भी जिले से कोई प्रस्ताव लांबित नहीं है। एक दिसम्बर से धान खरीदी शुरू होने के बाद रकबे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि रकबे में कोई परिवर्तन या संशोधन की

जुगत हो उसे 30 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाए। एक दिसम्बर के बाद साफेवर के लॉक कर दिया जाएगा। गिरदवरी के कार्य में अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। धान खरीदी के लिए

हजार गठन पॉलिटिक के बादवने खरीदी जा रही है। इस पॉलिटिक के बादवने का उपयोग केवल धान खरीदी करके सबसे पहले सीधे मितलों के पास भेजने के लिए किया जाएगा। पॉलिटिक बैग का उपयोग चावल रखने के लिए नहीं किया जाएगा।

धान बेचने वाले किसानों की संख्या के साथ रकबा बढ़ने से किसानों की सुविधा के लिए राज्य में लगभग 260 नवीन धान उपार्जन केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों में चतुर्था निर्माण सहित खरीदी केंद्र के चारों तरफ सूरक्षा के लिए फेरेट की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम, बारदाना, तापमपी, कांटा-बांड सत्यान, मास्कर मीटर, बोर्ड लगाने का कार्य खरीदी शुरू होने से पूर्व पूरा कर अनिवार्य रिपोर्ट अपलोड करने के निर्देश दिए गए। राज्य के खरीदी केंद्रों में दो चरणों में 7 हजार 620 खरीदारी का निर्माण करने की स्वीकृति दी गई है।

एक दिसम्बर से धान खरीदी के लिए टोकन मिलेगा 27 नवम्बर से	टोकन की वैधता अवधि एक सप्ताह	एक दिसम्बर के बाद रकबे में नहीं होगा कोई परिवर्तन	खरीदी के केंद्रों में किसानों की सुविधा का रखे विशेष ध्यान	अन्य राज्यों से धान आयात को रोकने की जिम्मेदारी जिला-पुलिस प्रशासन और संबंधित विभाग की
श्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी कमिश्नरी और कलेक्टरों से कहा कि एक दिसम्बर से राज्य में धान खरीदी शुरू होगी। राज्य में धान खरीदी का कार्य मुख्यमंत्री	अपर मुख्य सचिवों ने राज्य के सभी कमिश्नरी और कलेक्टरों से कहा कि एक दिसम्बर से राज्य में धान खरीदी शुरू होगी। राज्य में धान खरीदी का कार्य मुख्यमंत्री	अपर मुख्य सचिवों ने राज्य के सभी कमिश्नरी और कलेक्टरों से कहा कि एक दिसम्बर से राज्य में धान खरीदी शुरू होगी। राज्य में धान खरीदी का कार्य मुख्यमंत्री	अपर मुख्य सचिवों ने राज्य के सभी कमिश्नरी और कलेक्टरों से कहा कि एक दिसम्बर से राज्य में धान खरीदी शुरू होगी। राज्य में धान खरीदी का कार्य मुख्यमंत्री	अपर मुख्य सचिवों ने राज्य के सभी कमिश्नरी और कलेक्टरों से कहा कि एक दिसम्बर से राज्य में धान खरीदी शुरू होगी। राज्य में धान खरीदी का कार्य मुख्यमंत्री

केंद्र के चार काले कानूनों के खिलाफ ट्रेड यूनियन ने दिया धरना-प्रदर्शन

नव प्रदेश संवादता

रायपुर। संयुक्त ट्रेड यूनियन के तत्वावर में आज केंद्र के चार काले कानूनों के खिलाफ एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। ज्ञातव्य है कि केंद्र की मोदी सरकार ने मजदूरों के अधिकारों के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित किया है उसका देश भर में सभी ट्रेड यूनियन पूरवज विरोध कर रहे हैं। सरकार देश के मजदूरों को अपने काले कानूनों के तहत अपने अमीर मित्रों का बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। इस काले कानून को लागू कर मोदी सरकार को मान्य विरोधी काला चेहरा पूरे देश में देखा जाएगा। हम मजदूर निर्यात करना जानते हैं तो तानाशाही को विध्वंस करने की चेष्टाओं से जानते हैं। केंद्र के इस



काले कानून के विरोध को कांग्रेस पार्टी ने न केवल के संरक्षक सुरील सती अग्रवाल ने मोदी सरकार के अड़िल खैय्ये पर प्रहार करते हुए कहा कि मोदी सरकार अपने तानाशाही खैय्ये से बाजु आए और मजदूरों को उनके पूरे अधिकार को खानी बनाए जिसे वो अपने काले कानून से घुटाना चाहती है। प्रदेश का एक-एक मजदूर इस काले कानून को विरोध तब तक करेगा जब तक इसे वापस नहीं लिया जाएगा। इस अवसर पर संरक्षक सुरील सती अग्रवाल समेत सभी ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष व बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे।

भूपेश सरकार के जनहितैषी कार्यों की पीएम ने की प्रशंसा : विकास

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रकाश एल सचिव विकास दिवसरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के कार्यों की समीक्षा विस्तार से की और संतुष्टि ज्ञापन के बाद भूपेश सरकार के कार्यों की पूरी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से संबंधित मुद्दों (विधान सभा, अस्पताल का ढांचा, रामन तथा रोजगार आदि), प्रधानमंत्री आवास योजना (गणपत), प्रधानमंत्री आवासन भारत के अंतर्गत स्थानीय योजना, निगमित के रूप में खिले का विकास तथा आपराधजगणील्लर विभाग के संबंध चर्चा की और भूपेश सरकार के जनहितैषी कार्यों के संघटन एवं क्रियान्वयन पर संतुष्टि ज्ञापना। श्री दिवसरी ने कहा कि 15 सालों से छत्तीसगढ़ राज्य का बेहद गढ़ करने वाले

कर्मचारीवरो भाजपा नेताओं को प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए प्रशंसा पर सारा सूरत जवा करोना महामारी के समय जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूरे कांग्रेस सरकार जनहितैषी योजनाओं का क्रियान्वयन के निगमित की प्रस्तावित लगत लगभग 275 करोड़ 76 लाख 19 हजार रुपया होगा। विधानसभा भवन का निर्माण मुख्य रूप से भूतल-प्रथमाल-द्वितीय तल के रूप में किया जाएगा। भूतल में विधानसभा की सर्वकारी के लिए सदन, विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रियों के कक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष के कार्यालय, नेता

जल्द शुरू होगा विधानसभा भवन और दो जल परियोजनाओं के निर्माण का कार्य

परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति ने किया अनुमोदन

नव प्रदेश संवादता

रायपुर। मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग द्वारा नया रायपुर के सेक्टर-19 में निर्मित किए जाने वाले नए विधानसभा भवन और जल संसाधन विभाग द्वारा विलसपुर जिले के खारंग-अहिल जलसंधि परियोजना और छपरादोला पीछ जलसंधि परियोजना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेसी ने नया रायपुर के सेक्टर-19 में निर्मित किए जाने वाले नए विधानसभा भवन के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए विधानसभा भवन के निर्माण की प्रस्तावित लगत लगभग 275 करोड़ 76 लाख 19 हजार रुपया होगा। विधानसभा भवन का निर्माण मुख्य रूप से भूतल-प्रथमाल-द्वितीय तल के रूप में किया जाएगा। भूतल में विधानसभा की सर्वकारी के लिए सदन, विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रियों के कक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष के कार्यालय, नेता



मुख्य सचिव ने निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश

नव प्रदेश संवादता

रायपुर। मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में एन.एम.डी.सी. परियोजना निधि हेतु गठित हाइड्रॉकर कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में बस्तर संभाग में एन.एम.डी.सी. के

समन्वय से किए जा रहे विकास कार्यों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी। श्री मण्डल ने बस्तर संभाग के लघु नवनेज इमली, विरीजी, तितुर, राहद, काजु आदि का गुणवत्तापूर्ण प्रसकरण करने और इसके माध्यम से क्वालिटी के अजीविका में सुधार करने में निर्देश भी दिए हैं। बैठक में वर्ष 2020-21 में बस्तर संभाग के सभी जिलों में एन.एम.डी.सी. द्वारा समुदायिक सहभागिता पर्य में

बताया कि 720 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से बिलासपुर जिले में अहिल नदी पर खारंग अहिल लिंक जलसंधि का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए आरक्ष जलसंधि परियोजना से पाप के द्वारा नदियों का जल जलसंधि तक लाया जाएगा। इस जलसंधि में कान्कित जल का इस्तेमाल बिलासपुर और रायपुर शहरों में पेयजल अर्गुति के लिए किया जाएगा। साथ ही नदियों के किनारे बसे 208 गांवों की 56285 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधा भी उल्लव्य हो सकेगी।

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की मीटिंग में मंत्री अनिला भोड़िया ने छत्तीसगढ़ में दियागजनों के पुनर्वास के लिए रखे कई प्रस्ताव

जिला दियागज पुनर्वास केंद्र और राष्ट्रीय सहायक उपकरण केंद्र स्थापित करने की मांग की

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों की ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हुई श्रीमती भोड़िया

नव प्रदेश संवादता

रायपुर। समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भोड़िया गुरूवार को केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित दियागजता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की ऑनलाइन बैठक में राजधानी रायपुर से शामिल हुईं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में दियागजों के पुनर्वास और कल्याण संबंधी कई प्रस्ताव केन्द्रिय सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखे। उन्होंने बोर्ड के समक्ष जलसंधि में दियागजों के लिए जिला दियागज पुनर्वास केंद्र, राष्ट्रीय सहायक उपकरण केंद्र, भवनसिंह रोडगंज के पुनर्वास के लिए संस्था की स्थापना और नेशनल हेरिटेजिड फ़र्नेस एवं



जलसंधि पर कारपरेशन को दियागजों के लिए पुनः राशि प्रदान करने हेतु निर्देशित किए जाने की मांग की।

मंत्री श्रीमती भोड़िया ने बताया कि राज सरकार दियागजन के हितों के लिए लगातार प्रयास कर रही है। श्रीमती सेना में अब दियागजन की भागीदारी बढ़ने लगी है। पिछले वर्षों में 11 से अधिक पदों में दियागजनों की भर्ती की गई है। छत्तीसगढ़ में दियागजनों को मुख्य धारा में शामिल करने और उनके स्वावलम्बन के लिए खाद्य प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ निःशुल्कन वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है। निगम द्वारा दियागजों को खाद्य प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में कोविड-19 के कारण दियागजनों द्वारा खाद्य आपस करने में कठिनाई आ रही है। निगम में वित्त 2 वर्षों से नेशनल हेरिटेजिड फ़र्नेस एवं जलसंधि पर कारपरेशन, नई दिखी द्वारा व्यवस्थापन हेतु प्रिचिवां को परामर्श दियागजनों के अधिकार पुनर्वास हेतु राशि उल्लव्य नहीं कराई जा सकी है। इस हेतु नेशनल हेरिटेजिड

फ़र्नेस एवं डेकलपमेंट कारपरेशन को पंथां बैंक गारंटी दी गई है। श्रीमती भोड़िया ने अनुरोध किया कि नेशनल हेरिटेजिड फ़र्नेस एवं डेकलपमेंट कारपरेशन को राज्य के दियागजनों के लिए राशि प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाए, ताकि दियागजनों को उनके आर्थिक पुनर्वास से जोड़ा जा सके। श्रीमती भोड़िया ने राज्य में राष्ट्रीय सहायक उपकरण केंद्र की स्थापना के लिए आवश्यक संयोग की मांग की।

समन्वय समिति द्वारा विद्युत अधिनियम 2020 का पुरजोर विरोध

पाँवर कंपनी मुख्यालय सहित प्रदेशभर में प्रदर्शन



रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कर्मचारी-अभिपत्ता समन्वय समिति के तत्वधनव्य 2020 का विरोध करते हुए यह भी निवेदन किया है कि पुरानी पुरान योजना लघु की जगह और निजीकरण के लिए बिट डब्ल्यूएमेट जो जारी किया गया है उसे वापस लिया जाये। कर्मियों द्वारा यह भी मांग रखी गई है कि जो स्थानीय कार्य है उसके लिए स्थानीय निगुति के जिले तथा स्थिति आधार पर कर्मियों की भर्ती कर जो शोणन किया जा रहा है उसे बंद किया जाये। धन्या प्रदान के दौरान कर्मियों ने इस बात की और भी ध्यान आरुष्ट किया है कि केवल राज्य की तरह भी राज्य के विजनी अधिकारियों के विरुद्ध विरुद्ध पुरजोर प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचव, हरिणाणा, पंडिम बंगाल के किसान संघों ने भी विद्युत अधिनियम 2020 का घोर विरोध किया है। राजधानी रायपुर में विद्युत कर्मचारी मुख्यालय

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कर्मचारी-अभिपत्ता समन्वय समिति के तत्वधनव्य 2020 का विरोध करते हुए यह भी निवेदन किया है कि पुरानी पुरान योजना लघु की जगह और निजीकरण के लिए बिट डब्ल्यूएमेट जो जारी किया गया है उसे वापस लिया जाये। कर्मियों द्वारा यह भी मांग रखी गई है कि जो स्थानीय कार्य है उसके लिए स्थानीय निगुति के जिले तथा स्थिति आधार पर कर्मियों की भर्ती कर जो शोणन किया जा रहा है उसे बंद किया जाये। धन्या प्रदान के दौरान कर्मियों ने इस बात की और भी ध्यान आरुष्ट किया है कि केवल राज्य की तरह भी राज्य के विजनी अधिकारियों के विरुद्ध विरुद्ध पुरजोर प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचव, हरिणाणा, पंडिम बंगाल के किसान संघों ने भी विद्युत अधिनियम 2020 का घोर विरोध किया है। राजधानी रायपुर में विद्युत कर्मचारी मुख्यालय

[illegible]

बाद इस पूरे मानले पर फर्जी तरिके से बिल बना कर गवन करने की आशंका जाहिर किया जा रहा है।

[illegible]

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पणडी से मुद्रित कर बिस्मिल चौक छोटादाया रायपुर से प्रकाशित।
 *फोन नं. ०७७१-४०३५६०३, RNI NO CHH/HHN/2012/41806/ टाक मंडीरा कान्ठ मीनी/आमचर्चा मीनी/४०/२०१२-२०१३

2 लाख 82 हजार राशन कार्डधारियों को अब टेबलेट से नहीं, थम लगाने से ही मिलेगा राशन

वन नेशन, वन कार्ड लागू होने के पहले शुरू हुआ ट्रायल, गाइडलाइन जारी

नवप्रदेश संवाददाता

कोरबा। कोरोना संक्रमण अभी कम नहीं हुआ है। गेज 150 से 200 के करीब मरीज मिल रहे हैं। दूसरी ओर राशन कार्डधारियों को अब थम लगाने पर ही राशन देने का निर्देश जारी किया गया है। पहले टेबलेट में फोटो खींचने के बाद राशन मिल जाता था। जिले में 2

लाख 82 हजार 708 राशन कार्डधारी हैं। इसमें से 39 हजार एपीएल कार्डधारक हैं। थम लगाने से पहले सैनित्वांजन जवरी है, लेकिन अधिकतर दुकानों में इसकी व्यवस्था नहीं रहती। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं होता। कोरोना संक्रमण की वजह से ही सोसायटी में राशन देने के पहले थम लगाने पर रोक लगा दी गई थी। 7 महीने बाद फिर से इसे लागू कर दिया है। टेबलेट में राशन कार्डधारियों के परिवार के किसी भी सदस्य का फोटो लेकर राशन दिया



जाता था। अब दुकान संचालक सीधे थम लगाने को कह रहे हैं। लेकिन सैनित्वांजन की व्यवस्था नहीं होने से कोरोना संक्रमण फैलने की संभावनाओं से इनकार नहीं

कई बुजुर्गों का अंगूठा स्कैन नहीं हो रहा

राशन कार्डधारियों में बुजुर्गों को अधिक परेशानी हो रही है। अंतराल के 60 क्वॉट पुनः स्कैनई श्रीवास ने बताया कि अंगूठा थिसे तो स्कैन नहीं होता। कई बार अपने बेटे को बुलाया पड़ता है वह फिर अन्य परिवार को बुलाकर स्कैन करवाता है। इन्हें बेटे ही स्कैन मिल पाता है।

राशन बांटने की क्षमता भी हो गई है कम

टेबलेट में एक दिन में 100 क्वॉट परिवारों को राशन मिलता था। अब 60 से 70 लोग ही राशन पा रहे हैं। जब तक थम का स्कैन नहीं होता, इंतजार करना पड़ता है। अनामोल के दुकान संचालक का कहना है कि लोगों की भी सह्यता करना चाहिए। अब थम कम करनी पड़ेगी।

10 से 15 मिनट का लाय रहता अतिरिक्त समय

टेबलेट में फोटो खींचने के बाद दुकान संचालकों को सुविधा थी। अब थम लगाने से 10 से 15 मिनट अधिक रुकना पड़ता है। एकाग्रता के अभाव में राशन देने में देर हो जाती है। राशन 10 क्वॉट से ज़्यादा बढ़ 2 घंटे बाद लगा। पहले 1 घंटे ही लगता था।

पुरे दुकान को सैनित्वांजन कराया जाएगा।

अतिक्रमण के नाम पर पंडो जाति एवं आदिवासियों के मकानों को गिराये जाने पर सख्त हुए मनेन्द्रगढ़ के विधायक

नायब तहसीलदार की दबंगई पर विधायक ने दिखाए कड़े तेवर

कहा भाजपा राज के भूमाधिकाओं को संरक्षण देकर पंडो जाति को समाप्त करना पड़ेगा मगरा, किसके आदेश पर की कारवाई

खडगवां जनपद पंचायत के ग्राम तनपुरा का मामला

नवप्रदेश संवाददाता

कोरिया/खडगवां। बीते बुधवार को खडगवां तहसील स्थित ग्राम पंचायत तनपुरा में नायब तहसीलदार के द्वारा बिना नोटिस, बिना वार्ड अन्य कोई सूचना के कार्यवाही से विशेष जनजाति वर्ग के सदस्य वेगा भुनगर आदिवासी दुहात में हैं। जिसकी शिकायत मिलते ही मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉ. विनय जायसवाल ने गुरुवार को मौके पर



उपस्थित होकर पूरे मामले की जानकारी ली और तत्काल नायब तहसीलदार खडगवां को दुरूपण के माध्यम से मौके पर उपस्थित होने की बात कही। विधायक मनेन्द्रगढ़ ने नायब तहसीलदार को भाजपा पटवारी, आर आर आर को भेज कर खुद मौके से नदारत दिव। जिसकी शिकायत विधायक मनेन्द्रगढ़ ने कलेक्टर कोरिया से

की और मौके पर उपस्थित अधिकारियों को जमकर पटवारा देने के निर्देश दिए हैं। और उसके विपरीत करने हुए भूमाधिकाओं के अवैध मकानों के दस्तावेजों की जांच कर कार्यवाही की बात कही। और पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार पर प्रशासनिक कार्यवाही की बात करते हुए कलेक्टर को पूरे मामले से संज्ञान

पीड़ित ने यूं बताया आपबीती

वाणीय बेचना ने जलजाली देते हुए बताया कि अगर हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में काम करना रहे तो उसका कोई प्रमाण है तो हमें दिखाए। स्थानीय प्रशासन ने आज दिवस से पहले कमीशन में ही नोटिस भेजा न ही कोई वार्ड तहसीलदार को देकर और बीते दिवस प्रशासन तहसीलदार के द्वारा हमें मकान को गिरा दिया गया। जो हमें दस्तावेज से पते है। जबकि इस भूमि पर हमारी तीन पीढ़ियों का कब्जा दिखाए पर दर्ज है। इसका ही वही दूसरे वाणीय तनपुरा पटवारा देकर तहसीलदार पर इतने धमकाते हुए वार्ड गैलरी करवा का आदेश दिया और उसका भी तहसीलदार ह। अपने दिमाग में देव लो ऐसी धमकी दिए जाने से वेगा खडगवां आदिवासी परिवार दहलाते हैं।

दिलाना गया है।

ये है पूरा मामला

जानकारी अनुसार मनेन्द्रगढ़ की दोपहर में खडगवां के नायब तहसीलदार भगवान दास कुशवाहा मनेन्द्रगढ़ को ग्राम पंचायत तनपुरा पटवारी और बेका पटवारा नावापिता भुनगर के द्वारा अपने पता का कब्जा दुहातवां करके दिखा दिया गया। जबकि ऊंच भूमि पर सन 1948-49 के रिकॉर्ड

पर बेका पिता नावापिता के नाम पर कब्जा दर्ज है और ऊंच भूमि पर वेगा परिवार तीन पीढ़ियों से खेती बाड़ी करते हुए आ रहे हैं और अब ऊंच भूमि पर अपना मकान बना रहे थे। जिसको नायब तहसीलदार ने नियम कानून का हवाला देकर स्वयं इन्हें नियोम को रद्दकरा करके हुए अपने पता का कब्जा दुहातवां करके नियोमाधीन मकान को तोड़ दिया।

नहीं दिखा यूनिजन की हड़ताल का असर, हर जगह कोयला उत्पादन व डिस्पैच निर्बाध गति से



कोरबा। आम हड़ताल का कोयला जगत पर ख़ास असर नहीं पड़ा है। हर जगह उत्पादन जारी है। एमएससीएल के दीपका क्षेत्र, कुसमुंड, नेवा एवं कोयला क्षेत्रों में काम पहले की तरह चलता रहा। पंजदुर सामान दिनों की तरह उपस्थित बमबारी ट्यूटी पर चले गए। कोयला एमएससीएल इन्फो के भी काम सामान्य दिनों की तरह चल रहा है। मजदूरों को ट्यूटी पर जाने से कहीं रुका नहीं गया है। इन्फो के काम भी सामान्य दिनों की तरह चल रहा है। हड़ताल का कोई विशेष असर नहीं दिख रहा है।

केंद्र सरकार की कमिश्नरल महानि, निविन, श्रम विरोधी नीति, कृषि कानून के विशेष में एस श्रमिक संघटनों ने आज देखाया

हड़ताल किया, इस हड़ताल का असर औद्योगिक जिला कोरबा में मिल-जुला असर देखा गया है। एमएससीएल की सामाजिक कोयला उत्पादन होने वाली नेवा, कुसमुंड, दीपका खदान में हड़ताल का कोई असर नहीं रहा। नेवा में 12 ब कोयला कर्मचारी ही हड़ताल में शामिल हुए बाकि कुसमुंड खदान में हड़ताल में निरति के श्रमिक हड़ताल में शामिल हुए। दीपका में भी हड़ताल बेअसर साबित हुई है। तीन क्षेत्रों में कोयला का उत्पादन और डिस्पैच कार्य सामान्य दिनों की तरह जारी रही। कुसमुंड खदान से हमसेव ताप विद्युत सवर्ग नेगरा खदान से एनटीपीसी कोयला संरक्ष, व दीपका खदान से एनटीपीसी सीपत कोयला को कोयला आगुति बाजित नहीं हुई है।

राजिम मेला स्थल के लिए 54 एकड़ स्थल का चिह्नांकन

कलेक्टर ने किया विनित स्थल का मुआयना
अधोसंरचना विकास में आगामी तेजी



विधायक ने की कार्य प्रगति की समीक्षा :

इस मौके पर राजिम डेवर हाउस में विधायक अमिर्ता दुलाल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर कार्य प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने राजिम मेला के लिए विनित जमीन और उसमें अधोसंरचना विकास के लिए की जा रही है। बैठक में श्री दुलाल ने हाल की सभी प्रस्तावित और स्वीकृत कार्य सारांश सौ में गुणावत के सारांश पढ़ा। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की खराबता आने पर उन्हें अज्ञात करवा। श्री दुलाल ने सड़क, पुलिका और सुविधा विभाग को अधिकारी पुरावों के निर्देश दिए, साथ ही हाल की कमी में किसी तरह की लापरवाही बर्तन नहीं की जावनी। इस मौके पर कलेक्टर मिलेन्द्रगढ़ देवरहाउस, अर्धजमीन अधिकारी (सुपर) जी डी बाली, तहसीलदार ओ. पी. नाग, लोक निर्माण विभाग के कार्यवाहक अधिकारी श्री एस.आर. जाटव एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।

माता मंदिर सहित अनेक आवश्यक अधोसंरचना निर्माण के लिए अधिकारियों से चर्चा की।

कलेक्टर ने कहा की आवश्यकता पड़ने पर इन स्थलों पर निजी जमीनों का भू-अंजन

कर सकते हैं जमीन दी जाएगी। उन्होंने पटवारी को आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मौजूद परसा का सीमांकन करने के लिए राजस्व विभाग को निर्देश दिए।

एनएमडीसी को एनआईपीएम ने नेशनल एचआर बेस्ट प्रेक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया

हैदराबाद। देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क खनन कंपनी एनएमडीसी को नेशनल एंटीट्रस्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट (एनआईपीएम) ने नेशनल एचआर बेस्ट प्रेक्टिस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया। ग्लोबल वर्ग का अवार्ड अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम कार्यवाही पद्धतियों को मान्यता प्रदान करता है। जिससे बेहतर परिणामों के लिए मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। एनएमडीसी को इसकी अद्वितीय संसाधन प्रणाली के लिए अवार्ड मिला।



मानव संसाधन पद्धतियों के लिए सम्मानित किया गया। एनएमडीसी को यह विशेष सम्मान उद्योग का नेतृत्व करने वाली तथा प्रगतिशील मानव संसाधन पद्धतियों के लिए प्रदान किया गया है।

बांड को अपने कार्यवाह की आकांक्षाओं तथा विचारों के अनुरूप बनाने की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अवार्ड का उद्देश्य कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुरूप मानव संसाधन कार्यक्रम तथा नीतियों बनाने वाले सारजन की मान्यता प्रदान करना है। एनएमडीसी सिस्टिफ एक ऐसी इको प्रणाली का सुनन करने में सक्षम रहा है जो कर्मचारियों को अपने कौशल का विकास करने की सहायता प्रदान करता है तथा रणनीतिक सफलता के लिए मानव संसाधन पद्धतियों के महत्व को प्रदर्शित करता है।

नव प्रदेश Health

Online C.G.

डिवाइन हेल्थ सेंटर - 0771-4035602, 99932-55740

सिटीयर्स मरीजों का उत्कृष्ट ईलाज (उपचर दारों में), सर्वसुविधापूर्ण आईसीयू आर्युकिंक अपैरेटन थियेटर सभी प्रकार की जांच सुविधा

बांढिया हॉस्पिटल

कोविड मरीजों के ईलाज के लिए अलग व्यवस्था

24 घंटे उपलब्ध सुविधाएं

रजा तालाब रोड, रायपुर, फोन : 0771-2425009, 2424737

वासुदेव हॉस्पिटल

माहेश्वर बाजार रोड, जिलापालिका रोड, रायपुर, फोन : 77228-24988

ऑप्टिकल हार्ड सॉलरम में अपराधन विधिर, डन रोड, सोनीबाग, 8. वी.पी. एच. रायपुर की सुविधा प्रदान की जाएगी।

ई.सी.जी. की सुविधा उपलब्ध है

डॉ. गजाला सिद्धीकी

माहेश्वर बाजार रोड, जिलापालिका रोड, रायपुर, फोन : 77228-24988

ऑप्टिकल हार्ड सॉलरम में अपराधन विधिर, डन रोड, सोनीबाग, 8. वी.पी. एच. रायपुर की सुविधा प्रदान की जाएगी।

ई.सी.जी. की सुविधा उपलब्ध है

डॉ. आशीष गोयलका

माहेश्वर बाजार रोड, जिलापालिका रोड, रायपुर, फोन : 77228-24988

ऑप्टिकल हार्ड सॉलरम में अपराधन विधिर, डन रोड, सोनीबाग, 8. वी.पी. एच. रायपुर की सुविधा प्रदान की जाएगी।

ई.सी.जी. की सुविधा उपलब्ध है